भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 205

जिसका उत्तर सोमवार 24 जून, 2019 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकारी राजसहायता

205. श्री के.सी. राममूर्ती:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राजसहायता देने वाले देशों का पता लगाया है, जिसमें निजी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली कंपनियां भी शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वामियों को राजसहायता देने वाले देशों का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या अब सरकार निजी इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों को दी जाने वाली राजसहायता को वापस लेने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या यह ऑटो उद्योग के लिए एक धक्का है; और

(ङ) क्या सरकार ने पारिस्थितिकी तंत्र और तेल बचाओ अभियान पर इसके प्रभाव के बारे में विचार किया हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ): भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना के चरण-I के दौरान प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर और उद्योग एवं उद्योग संघों सहित सभी स्टेकहोल्डरों से परामर्श करने के बाद, भारी उद्योग विभाग ने फेम इंडिया योजना के चरण- II को अंतिम रूप दिया और तदनुसार दिनांक 08 मार्च, 2019 को इसे अधिसूचित किया जो दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से आरंभ होकर तीन वर्षों की अवधि के लिए है। जीवाश्म ईंधनों और पर्यावरणीय प्रदूषण की कमी पर इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रभाव को देखते हुए ई-दुपहिया वाहनों के अलावा, जहां प्रोत्साहनों के माध्यम से निजी स्वामित्व वाले दुपहिया वाहनों की भी सहायता की जा रही है, योजना का यह चरण मुख्यतः सार्वजनिक एवं साझा परिवहन पर केन्द्रित है।

*****